पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.589

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.- 2016, थाना-सरैया, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर से उदभूत।

==========

तारकेश्वर राम, पुत्र- धुरेन्दर राम, ग्राम के निवासी- सरैया बसंत, थाना- तरैया, जिला- सारण, छपरा के निवासी हैं।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/गण

==========

साथ

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 785

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.- 216, थाना-सरैया, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर से उदभूत।

==========

सुरेश साहनी, पुत्र-स्वर्गीय सोनेलाल साहनी, ग्राम के निवासी-चक्की, सोहागपुर, थाना पारो, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/गण

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 374 (2)-दोषसिद्धि के खिलाफ अपील-पीड़ित-एक भौतिक गवाह-जिस कथन पर अभियोजन आधारित है उसे प्रकट करने हेतु आवश्यक गवाहों को अभियोजन को अक्टूबर आह्वान करना चाहिए ।परीक्षण यह है कि क्या वह उस कथा को प्रकट करने के लिए आवश्यक गवाह है जिस पर अभियोजन पक्ष आधारित है। (नारायण और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1958 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 47, पैरा 13 संदर्भित)।(पैरा-16,17,17.1)।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-प्रतिपरीक्षा-जांच अधिकारी-एक सामग्री गवाह-जांच अधिकारी की गैर-जांच-सामग्री की कमी पैदा करता है- अभियोजन मामले में उचित संदेह पैदा करता है (मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 80, पैरा -39), (पैरा-19,19.1)। **प्रतिपरीक्षा के लिए गवाह प्रस्तुत किया जाना।यदि ऐसा नहीं होता है-तो रक्षा प्रति परीक्षण करने का अवसर खो देती है।** (यू. पी. राज्य एवं एक अन्य बनाम एन. आर. वी. जग्गो उपनाम जगदीश और अन्य (1971) 2 एस. सी. सी. 42, पैरा -15) ; राम रंजन राय बनाम एम्परर (आई. एल. आर. 42 कैल 422:19 सीडब्ल्यूएन 28:27 आईसी 554; स्टीफन सेनिवरत्ने बनाम किंग (ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 289) (पैरा 18,18.1) **जांच अधिकारी की गैर-परीक्षण गैर-घातक-जब अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है-अभियुक्त को एक गवाह के प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार (लाहू कमलाकर पाटिल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 417, पैरा-18)।(पैरा-20,20.1)**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-(पैरा-21,23, 24) - धारा 164-बयान दर्ज करने में देरी-पीड़ित परिवार के साथ-पहचान का कोई स्रोत नहीं-केस डायरी पर भरोसा-किसी अन्य ठोस सबूत के अभाव में-अभियोजन उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा-अपील की अनुमति है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.589

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.- 2016, थाना-सरैया, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर से उदभूत।

==========

तारकेश्वर राम, पुत्र- धुरेन्दर राम, ग्राम के निवासी- सरैया बसंत, थाना- तरैया, जिला- सारण, छपरा के निवासी हैं।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/गण

==========

साथ

2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 785

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.- 216, थाना-सरैया, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर से उदभूत।

==========

सुरेश साहनी, पुत्र-स्वर्गीय सोनेलाल साहनी, ग्राम के निवासी-चक्की, सोहागपुर, थाना पारो, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रत्यार्थी/गण

==========

उपस्थिति:

(2016 के आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 589 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री राधा मोहन सिंह, अधिवक्ता

श्री सत्यम आनंद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो. अभि.

(2016 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 785)

अपीलार्थी के लिए : श्री आरुणी सिंह, अधिवक्ता

श्री संदीप कुमार गौतम, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सत्य नारायण प्रसाद, सहायक लोक अभियोजक

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि : 16-01-2024

ये दोनों अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 374 (2) के तहत अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा सरैया थाना मामले सं.216/14, जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 'रु. 25,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने पर, अपीलार्थियों को एक वर्ष के लिए आर. आई. भुगतना होगा, से उत्पन्न होने वाले सत्र मुकदमे सं.934/14 में मुजफ्फरपुर के विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-11 द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 20.05.2016 की सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गयी हैं।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार हैः

सूचक, मंटू सिंह ने सरैया पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को एक लिखित शिकायत दी है जिसमें कहा गया है कि 17.06.2014 को 12:00 - 01:00 के मध्य रात में, उसके लगभग 7 साल के पुत्र का अपहरण, जब वह अपनी दादी के साथ सो रहा था कर लिया गया। जब मुखबिर की माँ 1:00 बजे रात में उठी, उसे अपना पोता नहीं मिला और उसने मुखबिर को सूचित किया और उन्होंने लड़के की तलाश शुरू कर दी। सूचक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर लड़के की तलाश शुरू कर दी और पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और उन्होंने पीड़ित लड़के की तलाश करने की भी कोशिश की।

3. श्री राधा मोहन सिंह, अपीलार्थी के विद्वान वकील को 2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.589 में, श्री आरुणी सिंह अपीलार्थी के विद्वान वकील, 2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.785 में और श्री सुजीत कुमार सिंह और श्री सत्य नारायण प्रसाद, उत्तरदाता- दोनों अपीलों में राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुना।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि पीड़ित के पिता, अभि. साक्षी -1 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, उन्होंने वर्तमान अपीलार्थियों के नाम नहीं दिए हैं। हालांकि, एक आरोपी के तथाकथित इकबालिया बयान के आधार पर, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आरोप लगाया गया कि पीड़ित लड़के को आरोपी तारकेश्वर राम की झोपड़ी से बरामद किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक और महत्वपूर्ण पहलू को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि वह जांच अधिकारी और पीड़ित लड़के से पूछताछ करे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त

महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह करने का अवसर खो दिया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि का विवादित आदेश पारित करते समय, निचली अदालत ने केस डायरी पर भरोसा किया है और सी. डी. आर. के संबंध में संदर्भ भी दिया गया है, हालांकि, सी. डी. आर. प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके अलावा, निचली अदालत ने केस डायरी को संदर्भित करते समय त्रुटियां की और वह भी जब अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि निचली अदालत ने भी केवल पीड़ित के बयान पर भरोसा किया है जो संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। हालाँकि, उसके बाद लड़के को निचली अदालत के समक्ष जिरह के उद्देश्य से पेश नहीं किया गया था।

5. विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क है कि संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय भी, संबंधित मजिस्ट्रेट ने भी पीड़ित से यह पता लगाने के लिए सवाल यह सुनिश्चित करने के वास्ते नहीं किया है कि उक्त पीड़ित लड़का सही तथ्यों को बताने की स्थिति में है या नहीं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित को 22.06.2014 को पाया गया था, हालांकि, सूचना देने वाला और अन्य रिश्तेदार पुलिस स्टेशन में उक्त पीड़ित लड़के से मिले और उसके बाद लड़के को दो दिनों की अवधि के बाद यानी 24.06.2014 को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के उद्देश्य से ले जाया गया और इसलिए, सभी संभावनाएं हैं कि दो दिनों की अवधि के दौरान, सूचना देने वाले और अन्य रिश्तेदारों ने उक्त पीड़ित को पढ़ाया होगा। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी सुरेश साहनी को झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह एक किरायेदार था और सूचक और कथित अभियुक्त के बीच किराये का विवाद था। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों/दोषियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे

साबित करने में विफल रहा है, तो निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाए और इस तरह इन दोनों अपीलार्थियों को बरी कर दिया जाए।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(i) **नारायण और अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1958 में एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 47** में प्रतिवेदित

(ii) **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम जग्गो उर्फ़ जगदीश और अन्य, (1971) 2 एस.सी.सी 42** में रिपोर्ट किए गए

(iii) **मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2023 में एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 80** में एक और अनुरूप मामला प्रतिवेदित किया गया।

(iv) **लाहू कमलाकर पाटिल और एक अन्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एस.सी.सी. 417** में सूचित

7. दूसरी ओर, विद्वान एपीपी ने इन दोनों अपीलों का जोरदार विरोध किया है। विद्वान एपीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पीड़ित ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान देते हुए कहा है कि आरोपी सुरेश साहनी और 4-5 अन्य लोगों ने रात के समय जब वह अपनी दादी के साथ सो रहा था, उसका अपहरण कर लिया था। स्वयं पीड़ित द्वारा दिए गए संस्करण पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाले को टेलीफोन कॉल किया गया था और रु.10,00,000/- की मांग भी इस धमकी के साथ की गई थी कि वे सूचना देने वाले पुत्र को मार देंगे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को साबित कर दिया है और इसलिए,

निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, उसी का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। विद्वान एपीपी ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तर्क का भी उल्लेख किया है और उसके बाद प्रस्तुत किया है कि केस डायरी में पर्याप्त सामग्री है जिसे निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं/दोषियों के खिलाफ संदर्भित किया गया है। निचली अदालत ने सी. डी. आर. को भी संदर्भित किया है जो जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किया गया था, जिसके आधार पर सुरेश साहनी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद, उसके इकबालिया बयान के आधार पर, लड़के को वास्तव में तारकेश्वर राम की झोपड़ी से बरामद किया गया था। लड़के को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहां पीड़ित लड़के ने विशेष रूप से सुरेश साहनी का नाम लिया है। इसलिए विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष इन दोनों विद्वान अपीलार्थी /दोषी के खिलाफ उचित संदेह से परे वाद प्रमाणित कर चुका है, तो यह अदालत आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैं।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलेगा कि सूचना देने वाले, जो पीड़ित लड़के के पिता हैं, ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनके पुत्र का अपहरण रात के समय 17.06.2014 को किया गया था और उसके बाद उसका बेटा, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, लापता है। इसके अलावा अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पंजीकरण के पश्चात, जाँच अधिकारी ने जाँच प्रारम्भ की एवं जाँच के क्रम में, उन्होंने गवाहों के बयां को दर्ज किया हैं। अभियोजन पक्ष का मामला है कि जब मुखबिर का आगे

का बयान दर्ज किया गया था, तो उसने अपने मोबाइल फोन पर कहा था की उसे एक कॉल आया था जिसमें संबंधित कॉलर ने *रंगदारी* (फिरौती) के रूप में रु.10,00,000/- की मांग की थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह भी है कि मुखबिर को धमकी भी दी गई थी कि अगर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उसके पुत्र को मार दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद जांच अधिकारी ने आगे की जांच की है और यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि उक्त जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने आरोपी सुरेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके इकबालिया बयान के आधार पर उसके घर से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इससे पहले सी. डी. आर. के आधार पर जांच अधिकारी आरोपी सुरेश साहनी के पास पहुंचे। इसके बाद, इकबालिया बयान के आधार पर, यह आरोप लगाया जाता है कि लड़के को तारकेश्वर राम की झोपड़ी से 22.06.2014 को बरामद किया गया था और उसके बाद उसे संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया था।

9. हालाँकि, यदि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की जांच/सराहना की जाती है, तो यह पता चलता है कि अभि. साक्षी-1, मुखबिर, मंटू सिंह, जो पीड़ित लड़के के पिता हैं, ने अपने बयान में कहा है कि लगभग 12:00 से 1:00 बजे रात के समय,17.06.2017 को उसका पुत्र उक्त गवाह की माँ के साथ सो रहा था। हालाँकि, उसके बाद लड़का नहीं मिला और इसलिए, उन्होंने अगले दिन सुबह लड़के की तलाश करने की कोशिश की और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त गवाह द्वारा आगे कहा गया है कि 18.06.2014 को उसके मोबाइल नंबर 9631433457 पर एक कॉल आया था और संबंधित व्यक्ति ने *रंगदारी* (फिरौती) के माध्यम से रु.10,00,000/- की मांग की थी और धमकी भी दी गई थी कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उसके पुत्र को मार दिया जाएगा। इसलिए, उन्होंने उक्त टेलीफोन नंबर पुलिस को प्रदत्त किया है। इसके बाद तलाशी के दौरान तारकेश्वर राम के घर से उसका पुत्र बरामद किया गया और तारकेश्वर

राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त तलाशी के दौरान एक सुरेश साहनी को भी गिरफ्तार किया गया था।

9.1 जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा कि तलाशी के दौरान, वह पुलिस के साथ नहीं गया है। उसने यह भी नहीं देखा है कि उसके पुत्र को पुलिस ने कहाँ से बरामद किया था। जिस व्यक्ति ने टेलीफोन पर *रंगदारी* की मांग की है, उसकी आवाज उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी। इससे पहले कि लड़के को पुलिस द्वारा अपना बयान दर्ज करने के उद्देश्य से अदालत में पेश किया जाए, वह पुलिस स्टेशन में अपने पुत्र से मिला और जब उसका बेटा पुलिस स्टेशन में था तो कई लोग पुलिस स्टेशन भी गए और पुलिस स्टेशन में ऐसे सभी लोगों ने लड़के से बात की।

10. अभि. साक्षी-2, हेमंती देवी, पीड़ित लड़के की दादी, ने बयान दिया है कि वह अपने पोते,अर्थात सनी राज के साथ सो रही थी और जब वह 12:00 - 01:00 बजे रात में उठी और उसे अपना पोता नहीं मिला। उसने अपने पुत्र को सूचित किया और लड़के की तलाश शुरू कर दी। इस गवाह ने अपनी मुख्य प्रति-परीक्षण में यह भी कहा कि अगले दिन, उसके पुत्र को एक फोन कॉल आया और फोन करने वाले ने *रंगदारी* (फिरौती) के रूप में रु.10,00,000/- की मांग की थी। बयान में यह भी कहा गया कि इसके बाद, फोन कॉल के आधार पर, पुलिस ने जांच शुरू की और पांच दिनों के बाद, पुलिस ने सरैया दियार में स्थित एक झोपड़ी से उसके पोते को बरामद किया। इस गवाह ने अपने मुख्य प्रति-परीक्षण में यह भी कहा कि आरोपी ने उसके पोते को मारने की धमकी दी थी।

10.1. अभि. साक्षी-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि जब उसके पोते का अपहरण किया गया था, तो वह सो रही थी और किसने उसके पोते का अपहरण किया था, वह देख नहीं सकी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उस झोपड़ी को नहीं देखा जहां

से उनके पोते को बरामद किया गया था। पीड़ित लड़के के अपहरण के बाद उसके परिवार के सदस्यों ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। इस गवाह ने अपनी जिरह में आगे कहा कि वह अपने पोते के बरामद होने के बाद पुलिस स्टेशन में उससे मिली थी। रंगदारी की मांग उनके पुत्र के मोबाइल फोन पर फोन कॉल के माध्यम से की गई थी। आरोपी ने धमकी दी कि अगर रु.1,00,000/- का भुगतान नहीं किया गया, तो लड़के को मार दिया जाएगा। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने *रंगदारी* की मांग के बारे में पुलिस को सूचित किया। यह गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे बताता है कि यह सच नहीं है कि उसका पोता अध्ययन में कमजोर था और वह घर से भाग गया था।

11. अभि. साक्षी-3, देवेंद्र सिंह ने अपने मुख्य प्रति-परीक्षण में कहा है कि घटना 17.06.2014 को रात 12:00-01:00 के मध्य हुई थी। उस समय वह सो रहा था। वह *हुल्ला* पर उठा और जानता था कि सनी राम का अपहरण कर लिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस आई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इस गवाह ने आगे कहा कि अगले दिन, पीड़ित लड़के के पिता मंटू सिंह को एक फोन आया और फोन करने वाले ने रंगदारी के रूप में रु.10,00,000/- की मांग की और धमकी भी दी गई कि यदि उक्त राशि नहीं दी गई तो लड़के को मार दिया जाएगा। पुलिस ने 22 तारीख को पीड़ित लड़के को बरामद कर लिया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

11.1.अभि. साक्षी-3 ने अपनी जिरह में कहा कि मंटू सिंह उसका चचेरा भाई है और सुरेश साहनी उसका किरायेदार था। उसने यह नहीं देखा कि पीड़ित लड़के का अपहरण कैसे किया गया। वह आरोपी तारकेश्वर राम को पहले से नहीं जानता था। लड़के की बरामदगी के बाद, पुलिस उसे सरैया पुलिस स्टेशन ले आई और उसके बाद वे लड़के को ले आए। इस गवाह द्वारा अपनी जिरह में आगे कहा गया है कि तारकेश्वर राम का घर सरैया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।

12. अभि. साक्षी-4, सुनैना देवी ने भी अपने परीक्षण-प्रमुख के पैराग्राफ-3 और 4 में लड़के के अपहरण और *रंगदारी* (फिरौती) की मांग के तथ्य का समर्थन किया। यह गवाह पाँच दिनों की अवधि के बाद पीड़ित लड़के के बरामद होने के तथ्य का भी समर्थन करता है।

13. अभि. साक्षी-5, संजीव कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मुज़फ़्फ़रपुर के रूप में संबंधित समय पर काम कर रहे थे। उसने कहा है कि अपहृत लड़के सनी राज को उसका बयान दर्ज करने के उद्देश्य से उसके सामने पेश किया गया था। उसने अपहृत लड़के सनी राज का बयान दर्ज किया था जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए गए।

13.1 जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़के की उम्र 7 साल थी। लड़का भी उससे पूछे गए सवाल को समझ रहा था।

14. अभि. साक्षी-6, संदीप कुमार जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने 24.08.2014 को जाँच का भार लिया था। उक्त गवाह ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

14.1 जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि औपचारिक प्राथमिकी उसकी लिखावट में नहीं थी। उन्होंने घटना स्थल का दौरा भी नहीं किया था। यही उनके पूर्ववर्ती ने किया था। जिस स्थान से लड़का बरामद किया गया था, उस स्थान पर भी वह नहीं गया था।

15. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित का बयान भी पेश किया है जो संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें पीड़ित लड़के ने कहा था कि वह अपनी दादी के साथ सो रहा था। उस समय सुरेश साहनी

और 4-5 अन्य लोग वहाँ आए और उन्हें *सरैया दियार* ले गए। उन्हें पाँच दिनों तक एक झोपड़ी में रखा गया था। संबंधित लोग उन्हें भोजन भी उपलब्ध करा रहे थे। 4-5 दिन बाद, पुलिस आई और उसे थाने ले गई और आज वह अपने माता-पिता के साथ आया है।

16. इस प्रकार, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, सूचना देने वाले ने अपने पुत्र के अपहरण की घटना के संबंध में प्राथमिकी दी, जिसे रात के समय 17.06.2014 को अपहरण कर लिया गया था। उक्त प्राथमिकी में उन्होंने किसी भी आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। अभि. साक्षी-1 के साक्ष्य से पता चलता है कि उसे अपने मोबाइल नंबर पर टेलीफोन कॉल आया था जिसमें संबंधित कॉलर ने *रंगदारी* (फिरौती) के माध्यम से रु.10,00,000/- की मांग की थी। धमकी भी दी गई थी कि अगर उक्त राशि नहीं दी गई तो उसके पुत्र को मार दिया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि सूचना देने वाले को किस मोबाइल फोन से कॉल आया है, यह रिकॉर्ड से नहीं दिखता है, हालांकि निचली अदालत ने पाया है कि सुरेश साहनी के घर से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और उसे सीडीआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि उक्त सी. डी. आर. की प्रति अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। निचली अदालत ने केस डायरी और आरोपी सुरेश साहनी के इकबालिया बयान का भी उल्लेख किया है। अभियोजन पक्ष जाँच अधिकारी की जाँच करने में विफल रहा हैं। जिसने जाँच की है, जिसके दौरान उसने सीडीआर के रूप में तथाकथित साक्ष्य एकत्र किए थे और आरोपी सुरेश साहनी का इकबालिया बयान भी दर्ज किया था। यह भी विवाद में नहीं है कि किसी ने पीड़ित लड़कों को जो तारकेश्वर राम की झोपड़ी से बरामद किया गया था नहीं देखा है। यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने संदीप कुमार का से अभी. साक्षी 6 के रूप में जाँच की हैं, जाँच अधिकारी, जिन्होंने अगस्त, 2014 में जांच का भार

लिया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त गवाह ने केवल संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने विशेष रूप से कहा है कि उसने घटना स्थल या उस स्थान की जांच नहीं की है जहाँ से पीड़ित लड़के को बरामद किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित लड़के से भी पूछताछ नहीं की है। पीड़ित लड़के का बयान वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक है क्योंकि वह अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण गवाह है। इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष पीड़ित लड़के और जांच अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा है, तो बचाव पक्ष ने उपरोक्त दो महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह करने का अवसर खो दिया है।

17. इस स्तर पर, हम नारायण एवं अन्य (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे **नारायण और अन्य (ऊपर)** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "भौतिक गवाह" के बारे में चर्चा की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पैराग्राफ-13** में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> *"**13**. तब सवाल यह है कि क्या रघबीर एक भौतिक गवाह था?यह एक स्वीकृत नियम है जैसा कि स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम किंग2 में न्यायिक समिति द्वारा कहा गया है कि "उस कथा के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक गवाह, जिस पर अभियोजन पक्ष आधारित है, निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाए जाने चाहिए। "यह देखा जाएगा कि यह परीक्षण कि क्या कोई गवाह वर्तमान उद्देश्य के लिए भौतिक है, यह नहीं है कि उसने बचाव के समर्थन में सबूत दिया होगा या नहीं। परीक्षण यह है कि क्या वह एक गवाह है "उस कथा के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक है जिस पर अभियोजन पक्ष आधारित है। "कोई गवाह इतना आवश्यक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह अभियोजन पक्ष के मामले के*

किसी भी हिस्से से बात कर सकता है या क्या किये गए साक्ष्य से पता चलता है कि वह इतना स्थित था कि वह उन तथ्यों का साक्ष्य देने में सक्षम होता जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता था। हालाँकि ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष उन सभी गवाहों को बुलाने के लिए बाध्य है जिन्होंने घटना को देखा होगा और इसलिए सबूतों की नकल करें। लेकिन इसके अलावा, अभियोजन पक्ष को सभी भौतिक गवाहों को बुलाना चाहिए। "

17.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि जिस कथन पर अभियोजन पक्ष आधारित है, उसे सामने लाने के लिए आवश्यक गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह उस कथा के सामने आने के लिए आवश्यक गवाह है जिस पर अभियोजन पक्ष आधारित है।

18. **यू. पी. राज्य एक अन्य बनाम जग्गो एलियास जगदीश और अन्य (ऊपर),** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ-15** में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

*"**15.** हबीब मोहम्मद मामले में इस अदालत ने राम रंजन रॉय बनाम सम्राट [आई. एल. आर. 42 कैल 422: 19 सीडब्ल्यूएन 28:27 आई. सी. 554 में जेनकिंस, सी. जे. की टिप्पणियों का उल्लेख किया कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य किसी भी कीमत पर एक सिद्धांत का समर्थन करना नहीं है, बल्कि अपराध की जांच करना और अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करना है और एक लोक अभियोजक का कर्तव्य न्याय प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना है ताकि सभी उपलब्ध चश्मदीद गवाहों की गवाही अदालत के समक्ष हो। लॉर्ड रोशे ने स्टीफन सेनिवरत्ने बनाम किंग [ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 289:39 बम एल.*

आर. 1:164 आई. सी. 321] में जेनकिंस, सी. जे. की टिप्पणियों का उल्लेख किया और कहा कि जिस कथन पर अभियोजन पक्ष आधारित है, उसे सामने लाने के लिए आवश्यक गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाया जाना चाहिए कि उनकी गवाही का प्रभाव अभियोजन पक्ष के मामले के पक्ष में है या खिलाफ। यही कारण है कि हबीब मोहम्मद मामले में इस अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों में एक चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति एक निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकती है। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि रमेश चंद को जीत लिया गया था और इसलिए अभियोजन पक्ष रमेश को नहीं बुला सका। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि केवल इस आशय के एक आवेदन की प्रस्तुति कि एक गवाह को जीत लिया गया था, इस सवाल का निर्णायक नहीं था कि गवाह को जीत लिया गया था। ऐसे मामले में रमेश को आरोपी द्वारा जिरह के लिए पेश किया जा सकता था। इससे सही तथ्य सामने आए होंगे। अगर रमेश एक प्रत्यक्षदर्शी थे, तो अभियुक्त उसके साक्ष्य का परीक्षण करने के हकदार थे, विशेष रूप से जब लालू पर घटना के समय रमेश के साथ बात करने का आरोप लगाया गया था। ”

18.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा जिरह के लिए एक गवाह को पेश किया जाना है। वर्तमान मामले में, पीड़ित लड़का, जो अभियोजन पक्ष का भौतिक गवाह है, को जिरह के उद्देश्य से अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था और इस तरह बचाव पक्ष ने जिरह का अवसर खो दिया है।

19. **मुन्ना लाल (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पैराग्राफ-39** में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

*"**39.** दूसरा, हालांकि कहा जाता है कि अभि. साक्षी-4 5 सितंबर, 1985 को दोपहर 1:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और शव के कूल्हे पर चोट से निकलने वाले खून में एक गोली बरामद की, लेकिन उन हथियारों को जब्त करने के लिए कोई विचार योग्य प्रयास नहीं किया गया है। यह सच है कि केवल हथियार (हथियारों) को जिनसे जानलेवा हमला किया गया था को जब्त करने में विफलता/उपेक्षा ही अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, लेकिन यह तथाकथित चश्मदीद गवाहों, यानी अभि. साक्षी-2 एवं अभि. साक्षी-3 की मौखिक गवाही के सामने महत्वपूर्ण है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं पाया जा रहा है। गुम कड़ी जांच अधिकारी द्वारा प्रदान किए जा सकते थे, जो फिर से, कठघरे प्रवेश नहीं किया। गवाह से पूछताछ न होने से बचाव पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है और एक निष्कर्ष प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना आवश्यक है। जैसा कि पीडब्लू-4 ने बताया कि जांच अधिकारी गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सका, इसका कारण यह है कि उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। यह नहीं दिखाया गया था कि जांच अधिकारी किसी भी परिस्थिति में निचली अदालत में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए रास्ता नहीं छोड़ सकता था। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के मुद्दे पर विचार किया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से अभियोजन मामले में विशिष्ट अंतराल और अभि. साक्षी-2 और अभि. साक्षी-3 के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होने के कारण, यह न्यायालय वर्तमान मामले को ऐसे मामले के रूप में मानता है जहां जांच अधिकारी की परीक्षा महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। उसकी गैर-जाँच*

अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाने के अभियोजन पक्ष के प्रयास में एक भौतिक कमी पैदा करती है, जिससे अभियोजन मामले में उचित संदेह पैदा होता है।"

19.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि उक्त मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी, हालांकि एक भौतिक गवाह के रूप में उनका साक्ष्य आवश्यक था और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उनकी गैर-जांच अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाने के अभियोजन पक्ष के प्रयास में एक भौतिक कमी पैदा करती है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में उचित संदेह पैदा होता है।

20. **लाहू कमलाकर पाटिल (ऊपर)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कंडिका-18** में निम्न प्रकार से अवलोकन किया है:

*"**18.** कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभि. साक्षी 1 की गवाही की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने एफ. आई. आर. में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है लेकिन बहाना दिया है कि यह एक खाली कागज पर लिया गया था। यही बात जाँच अधिकारी द्वारा स्पष्ट की जा सकती थी, लेकिन किसी कारण से जाँच अधिकारी से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य [(1996) 2 एस. सी. सी. 317:1996 एस. सी. सी. (आपराधिक) 271], में इस न्यायालय ने कहा है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से, जब आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य [(2000) 9 एस. सी. सी. 153:2000 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1186], में यह राय दी गई है कि जब कोई भौतिक विरोधाभास*

सामने नहीं लाया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए एक गवाह के रूप में जांच अधिकारी की गैर-जांच का कोई परिणाम नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो निचली अदालत के न्यायाधीश ने और न ही उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के मुद्दे पर गौर किया है। अभिलेख पर लाई गई पूरी सामग्री के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्तमान मामला ऐसा है जहां हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं, विशेष रूप से जब सूचना देने वाले ने कहा है कि हस्ताक्षर तब लिए गए थे जब वह नशे की हालत में था, पंच गवाह मुकर गया था और अदालत में पेश किए गए कुछ सबूत संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में जगह नहीं पाते थे। इस प्रकार, यह न्यायालय अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य [(2001) 6 एससीसी 407:2001 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1148], रतनलाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(2007) 13 एस. सी. सी. 18:(2009) 2 एस. सी. सी. (आपराधिक) 349] और रविश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य [(2008) 16 एस. सी. सी. 561:(2010) 4 एस. सी. सी. (आपराधिक) 50] में कुछ परिस्थितियों की व्याख्या की है जहाँ जाँच अधिकारी की जाँच महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वर्तमान मामला वह है जिसमें जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी और उसकी गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले में एक कमी पैदा करती है। ”

20.1 उपरोक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से, जब आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। हालाँकि, ऐसी परिस्थिति में जहाँ जाँच अधिकारी की जाँच महत्वपूर्ण हो जाती है, जाँच अधिकारी की जाँच करना अभियोजन पक्ष

का कर्तव्य है और ऐसे मामलों में उसकी जाँच न करने से अभियोजन पक्ष के मामले में एक कमी पैदा हो जाती है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश किया है, जैसे कि सूचना देने वाला जो पीड़ित का पिता है, पीड़ित की दादी, सूचना देने वाले का चचेरा भाई और सूचना देने वाले के चचेरे भाई की पत्नी, उक्त गवाहों में से किसी ने वर्तमान अपीलार्थियों/दोषियों के नाम दिए हैं। मुखबिर के मोबाइल फोन के कॉल विवरण के आधार पर, आरोपी सुरेश साहनी को जांच अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोप है कि सुरेश साहनी के घर से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और उसके इकबालिया बयान पर लड़के को सह-आरोपी/सह-दोषी तारकेश्वर राम के घर से बरामद किया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने भी जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की है, कॉल विवरण, यानी सी. डी. आर. को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और उक्त दस्तावेज़ को विधिवत प्रदर्शित नहीं किया गया है। यहां तक कि अदालत के समक्ष इकबालिया बयान भी नहीं लाया गया, जिसके आधार पर सह-दोषी तारकेश्वर राम को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी झोपड़ी से यह आरोप लगाया गया है कि पीड़ित लड़के को बरामद किया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जांच अधिकारी की गैर-जांच से, बचाव पक्ष ने उक्त गवाह, यानी जांच अधिकारी से जिरह करने का अवसर खो दिया है और इस तरह अभियोजन पक्ष के मामले में खामियां हैं। एक बार फिर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित लड़के से भी पूछताछ नहीं की है, हालांकि संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान पर विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज करते समय भरोसा किया था।

22. इस प्रकार, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं ने सूचक के घर से पीड़ित लड़के का अपहरण कर लिया है और उन्होंने रंगदारी (फिरौती) के माध्यम से रु. 1,00,000/- की मांग की और उक्त राशि नहीं दिए जाने पर लड़के को मारने की धमकी दी।

23. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि तारकेश्वर राम की झोपड़ी से पीड़ित लड़के की बरामदगी भी विधिवत साबित नहीं हुई है। यद्यपि संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित लड़के का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उसका बयान मजिस्ट्रेट द्वारा उसके बरामद होने की तारीख से दो दिन की अवधि के बाद दर्ज किया गया था और जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने के लिए पेश किया गया था, तो वह अपने माता-पिता के साथ आया था न कि पुलिस के साथ।

24. इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। हमने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तर्क को भी देखा है और हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने केवल सी. डी. आर., जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित इकबालिया बयान और केस डायरी पर भरोसा किया है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, सी. डी. आर. को विधिवत साबित नहीं किया गया है। जांच अधिकारी जिसने उक्त सी. डी. आर. और इकबालिया बयान एकत्र किया है, उसकी भी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की जाती है और किसी अन्य ठोस सबूत के अभाव में केस डायरी पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए गंभीर त्रुटियां की है।

इसके अलावा, संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित लड़के के बयान से यह नहीं पता चलता है कि वह रात के समय अपीलार्थी सुरेश साहनी की पहचान कैसे कर सका। रिकॉर्ड से यह भी पता नहीं चलता है कि पीड़ित लड़के को तारकेश्वर राम की झोपड़ी से बरामद किया गया था क्योंकि इस मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है।

25. इसलिए, ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इन दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है। 2014 के सरैया थाना केस सं.216 से उत्पन्न सत्र मुकदमे सं.934/14 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-11, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के दिनांकित 20.05.2016 के आदेश के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। अपीलार्थी, अर्थात्, 2016 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.589 में तारकेश्वर राम और अपीलार्थी, अर्थात्, 2016 की आपराधिक अपील (खं. पी.) सं.785 में सुरेश साहनी को विद्वत निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। चूंकि ऊपर नामित दोनों अपीलार्थी जेल में हैं, इसलिए उन्हें यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायाधीश)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायाधीश)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।